

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार/टिहरी।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 20 जून, 2013

विषय: सी-डैप आधारित कृषि विकास कार्यक्रम-जिला योजनान्तर्गत बजट अवमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक उत्तराखण्ड के पत्र सं०-कृ०नि०/1780/लेखा-बजट /सी०डैप०/2013-14 दिनांक 11 जून, 2013 एवं राज्य योजना आयोग के पत्र सं०-631/362-वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2012 दिनांक 27 मई, 2013 एवं शासनादेश सं०-877/XIII-1/2013-5(23)2010 दिनांक 03 जून, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में सी-डैप आधारित कृषि विकास कार्यक्रम-जिला योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत जनपद हरिद्वार एवं टिहरी हेतु रु० 30.00 लाख (रुपये तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र०	जनपद	अनुदान सं०-17 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00- आयोजनागत-800-अन्य योजनाएं-91-जिला योजना-01-सी-डैप आधारित विकास कार्यक्रम-20-सहायक अनुदान	अनुदान सं०-30 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00- आयोजनागत-800-अन्य योजनाएं-91-जिला योजना-01-सी-डैप आधारित विकास कार्यक्रम-20-सहायक अनुदान	कुल राशि
1	हरिद्वार	06.00	04.00	10.00
2	टिहरी	15.00	05.00	20.00
	योग:	21.00	09.00	30.00

(रुपये तीस लाख मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र मुख्य कृषि अधिकारियों को व्यय हेतु इस प्रतिबन्ध के अधीन अवमुक्त कर दी जाय कि वे इसका उपयोग कृषि निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक माह की प्रगति अगले माह की दस तारीख तक अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

3- स्वीकृति धनराशि का उपयोग शासन के वर्तमान संसुगत आदेशों/निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज नियमों/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 में निहित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता संबंधी जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

4- बजट मैनुवल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण 10 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-8 पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 20 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-13 पर संकलित व्यय विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।



5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय में अनुदान सं०-17 एवं 30 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत प्रस्तर-1 की तालिकानुसार लेखाशीर्षक-2401 की मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शा०स०-183/XXVII(1)//2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से साफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत संलग्न विशिष्ट एलाटमैन्ट आई०डी० दिनांक 19 जून, 2013 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं०-284/XXVII(1)//2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं राज्य योजना आयोग के पत्र सं०-631/362-वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2013 दिनांक 02 मई, 2013 में दिए गए दिशा-निर्देशानुसार जारी किए जा रहे हैं।  
संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

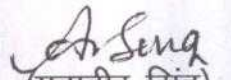
(देवेन्द्र पालीवाल)  
संयुक्त सचिव

संख्या-859 / XIII-I / 2013-5(23)2010 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मंडल, पौड़ी।
4. कृषि निदेशक उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी, उत्तराखण्ड।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मंडल, पौड़ी।
8. मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, हरिद्वार/टिहरी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
10. वरिष्ठ शोध अधिकारी, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर।
11. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से,

  
(महावीर सिंह)  
अनु सचिव